



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 1449/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2023-3(11)/मा०सं०(04)/2017(Vol-II) दिनांक 18.09.2023

कार्यालय-झाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या-217.23 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 10/2022/आई/178180/2022/फा०न०-10-19099/32/2022-22 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पension की मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) सतान को पारिवारिक पेशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी व्यवस्था/प्राविधान निर्गत किये गये हैं, को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

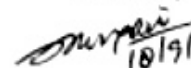
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1449/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2023/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झोंसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), मा०सं०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/जानपद-नव परियोजनायें/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति/पी०पी०एम०एम०, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या-217.23 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(रिफार्म)/(टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य)/(प्रशिक्षण)/(तापीय परिचालन)/(जानपद)/(औ०सं०)/(लेखा प्रशासन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झोंसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,


18/9/23

(तरुण कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-04)

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2022

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1155/दस-2/81, दिनांक 06 अगस्त, 1981, शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81ट0सी0, दिनांक 12 नवम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 निर्गत किये गये हैं।

2- उपरोक्त शासनादेशों में मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में आय के मानदण्ड का उल्लेख नहीं है।

3- सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यन्वय-ज्ञापन संख्या-1/17/2019-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 08 फरवरी, 2021 के प्रकरण-3, 4 एवं 6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है:-

उक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर, जीनवपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसा बच्चा अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता है, यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता के लिये भारत <http://e-governance.gov.in> से प्रमाणित की जा सकती है।

4- तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसा बच्चा/सहोदर, जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि वह अन्यो के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से निःशक्त बच्चे की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य कुटुंब पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

6- ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे/सहोदर को वर्तमान में कुटुंब पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के समय कुटुंब पेंशन करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकाया एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08 फरवरी, 2021 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगी, यदि निम्नलिखित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसी संतान अपनी जीविका उपार्जन नहीं करती/करती है, यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय पारिवारिक पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसी संतान, जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगा/होगी, यदि वह अन्यो के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता/करती है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से निःशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी संतान को वर्तमान में पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसी संतान को

पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

5- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थाएँ/शर्तें यथावत् रहेंगी।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोयागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मुख्य/परिचालिकाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणांकित संख्या है <http://shasanaadesh.up.gov.in> से मापायित की जा सकती है।